पटना में न्यायपालिका के अधिकार में

2015 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 9745

==========

आंचल द्विवेदी, पुत्र-श्री गिरिजा नंदन द्विवेदी, निवासी- 2/425 मंजुपुर डाकघर, थाना और जिला हमीरपुर (यूपी)

.... याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. मुख्य सचिव, बिहार, पटना के माध्यम से बिहार राज्य
2. प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार, पटना।
3. अपर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग। , बिहार सरकार, पटना।
4. पटना में उच्च न्यायालय अपने महानिबंधक के माध्यम से।
5. महापंजीयक, पटना उच्च न्यायालय, पटना।

.... उत्तरदाता/ओं

==========

न्यायिक निर्णय-- उच्च न्यायालय की स्थायी समिति के निर्णय के विरुद्ध सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ प्रभाग) द्वारा याचिका-- परिवीक्षा की गैर-दंडात्मक और गैर-कलंकित समाप्ति-न्यायिक जीवन का अचानक अंत-- अनुशासनात्मक जांच के बाद जांच अधिकारी द्वारा दोषमुक्ति-याचिकाकर्ता के खिलाफ जिला न्यायाधीश का पक्षपात-शिकायतें-अवैधता और समाप्ति की मनमानेपन-चुनाव का सिद्धांत-भारत संघ बनाम कर्नल जे.एन. सिन्हा; (1970) 2 एससीसी 458---न्यायिक समीक्षा के अधीन मनमाना निर्णय-- बैकुंता नाथ दास बनाम मुख्य जिला। चिकित्सा अधिकारी (1992) 2 एस. सी. सी. 458-बनाम भारत संघ (1998) 7 एस. सी. सी. 310-न्यायालय का हस्तक्षेप यदि आदेश दुर्भावनापूर्ण है या साक्ष्य या विकृत पर आधारित नहीं है-समयपूर्व अनिवार्य सेवानिवृत्ति आदेश की न्यायिक जांच की अनुमति है।

आयोजित किया गयाःन्यायिक अधिकारी की सेवाओं को समाप्त करने के लिए उच्च न्यायालय की स्थायी समिति के पास कोई सामग्री उपलब्ध नहीं है-बर्खास्तगी आदेश को दरकिनार कर दिया गया है-याचिकाकर्ता को सभी परिणामी लाभों, वरिष्ठता के साथ बहाल किया गया है।

पटना में न्यायपालिका के अधिकार में

2015 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 9745

==========

आंचल द्विवेदी, पुत्र-श्री गिरिजा नंदन द्विवेदी, निवासी- 2/425 मंजुपुर डाकघर, थाना और जिला हमीरपुर (यूपी)

.... याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. मुख्य सचिव, बिहार, पटना के माध्यम से बिहार राज्य
2. प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार, पटना।
3. अपर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग। , बिहार सरकार, पटना।
4. पटना में उच्च न्यायालय अपने महानिबंधक के माध्यम से।
5. महापंजीयक, पटना उच्च न्यायालय, पटना।

.... उत्तरदाता/ओं

==========

उपस्थिति :

याचिकाकर्ता/ओं के लिए	:	श्री जितेंद्र सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता
		श्री बजरंगी लाल, अधिवक्ता
		श्री यश सिंह, अधिवक्ता
		श्री ईशान सिंह, अधिवक्ता,
राज्य के लिए	:	श्री ए.बी.सिन्हा, जीए-8
		सुश्री कल्पना, अधिवक्ता
पटना उच्च न्यायालय के लिए	:	श्री संजीव कुमार, अधिवक्ता

==========

कोरमः माननीय मुख्य न्यायाधीश

एवं

माननीय श्री न्यायाधीश पार्थ सारथी,

सी.ए.भी निर्णय

(प्रतिः माननीय मुख्य न्यायाधीश)

तारीख : 27-09-2023

यह रिट याचिका एक सिविल जज (कनिष्ठ कोटि) जिसका न्यायिक करियर उच्च न्यायालय के स्थायी समिति के निर्णय द्वारा अचानक समाप्त हो गया था, द्वारा दायर की गई है। याचिकर्ता की सेवा, पर्यवेक्ष समाप्ति अधिसूचना दिनांकित 27.06.2014 के माध्यम से दिनांक 19.05.2014 के प्रभाव से समाप्त कर दिया गया था, जिसे प्रतिवादी के दृढ़ कथनानुसार समाप्ति सरलीकरण न तो दंडात्मक था एवं न ही कलंकित करने वाला।

2. दूसरी ओर, याचिकाकर्ता का कहना है कि निरंतर प्रशंसात्मक मूल्यांकन के साथ उनका कार्यकाल सफल रहा और पूरी समस्याएँ जिला न्यायाधीश द्वारा पली गई शत्रुता के कारण उत्पन्न हुईं; जिसके कारण उनके खिलाफ कई उकसाइ हुई शिकायतें की गईं। हालाँकि, इन सभी को कौंनसाइन कर दिया गया था, जिसके बावजूद सेवा समाप्ति अवैध और मनमाने तरीके से हुई ।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील श्री बजरंगी लाल के निर्देश पर विद्वान वरिष्ठ वकील श्री जितेंद्र सिंह ने बर्खास्तगी आदेश को रद्द करने और याचिकाकर्ता को पूर्ण परिणामी लाभों के साथ सेवा में बहाल करने का तर्क दिया। विद्वान वरिष्ठ वकील हमें अभिलेखों के माध्यम से ले गए, जो याचिकाकर्ता के खिलाफ उठाई गई शिकायत का संकेत देते हैं, जिसके परिणामस्वरूप एक चेतावनी दी गई; याचिकाकर्ता का भी एक सुसंगत रिकॉर्ड था और उनके प्रदर्शन को उत्कृष्ट किया गया था। इन सबके बावजूद, जिला न्यायाधीश द्वारा स्थायी समिति के समक्ष परिवीक्षा की घोषणा की सिफारिश पर, उक्त सिफारिश को दरकिनार कर दिया गया

और अधिकारी को उसकी परिवीक्षा की घोषणा करने से इनकार करने पर बर्खास्त कर दिया गया, जो इसको देखने से असमर्थनीय माना गया। हालांकि जिनमें से सौंपा गया जिसके बावजूद, समाप्ति एक अवैध एवं मनमाना तरीके से किया गया जो इसके समक्ष असमर्थनीय है।

4. याचिकाकर्ता ने न्यायिक सेवा में काफी समय बिताया था जब उनके न्यायिक कौशल या उनके प्रदर्शन के खिलाफ कोई सवाल नहीं उठाया गया था। उनके खिलाफ अनुशासनात्मक जांच शुरू की गई थी, लेकिन यह उनके दोषमुक्त होने में समाप्त हो गई थी। जाँच अधिकारी ने याचिकाकर्ता को उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों के लिए दोषी नहीं पाया और स्थायी समिति पूरी तरह से इससे सहमत थी। बरी किया जाना उस गवाह के कारण भी था, जिस पर आरोप है कि उसने जांच की कार्यवाही में शिकायत का मुद्दा उठाया था; जिसने जिला न्यायाधीश द्वारा उकसावे को भी स्वीकार किया था। किसी भी स्थिति में, दोषमुक्त किए जाने के बाद, स्थायी समिति के पास उन्हें बर्खास्त करने के लिए और कोई सामग्री नहीं थी। ***ट्रांसकोर बनाम भारत संघ एवं एक अन्य बनाम (2008) 1 एससीसी 125*** पर भरोसा रखा गया, चुनाव के सिधांत पर जोर देते है उच्च न्यायालय ने एक घरेलू जांच शुरू करने के लिए चुना है और यह अपराधी कर्मचारी के दोषमुक्त होने पर समाप्त हो गया है; उच्च न्यायालय को इस तरह की अनुशासनात्मक जांच या जांच की ओर ले जाने वाली शिकायत पर भरोसा नहीं करना चाहिए, ताकि याचिकाकर्ता की परिवीक्षा घोषित करने से इनकार करके उसकी सेवाओं को समाप्त किया जा सके।

5. ***एम. एस. बिंद्रा बनाम भारत संघ एवं अन्य बनाम (1998)7 एस सी सी 310*** पर भरोसा रखा गया ताकि 2022 के दीवानी अपील सं. 2023 पर 15.03.2022 को निर्णय लिया गया। बिना किसी साक्ष्य के आधार पर समाप्ति का आदेश और अभिलेखों से यथोचित रूप से उत्पन्न न होने वाले निष्कर्ष। यह प्रशासनिक

कार्रवाई को दूषित करता है और यहां तक कि एक समाप्ति सरलीकरणकर्ता को सेवा में बने रहने के लिए कर्मचारी की अक्षमता या अयोग्यता के बारे में एक वस्तुनिष्ठ संतुष्टि द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए; कम से कम रिकॉर्ड से पता चलता है।

6. ***अभय जैन बनाम राजस्थान में उच्च न्यायालय के न्यायाधिकार एवं एक अन्य*** मामले में दिनांक 15.03.2022 का निर्णय लिया गया। उक्त निर्णय से घोषित तथ्यों और कानून को विशेष रूप से पढ़ा जाता है ताकि यह आग्रह किया जा सके कि वर्तमान रिट याचिका एक समान आधार पर है। याचिकाकर्ता पूर्ण लाभों के साथ सेवा में बहाल होने का हकदार है।

7. हमने राज्य के विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री ए.बी. सिन्हा और उच्च न्यायालय के विद्वान स्थायी वकील श्री संजीव कुमार को भी सुना है।

8. उच्च न्यायालय द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि बर्खास्तगी दंडात्मक नहीं है और न ही यह याचिकाकर्ता पर कोई कलंक लगाती है और यह केवल स्थायी समिति के इस निष्कर्ष पर पहुंचने के कारण एक समाप्ति सरलीकरण है कि याचिकाकर्ता का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं है और उसे सेवा में जारी रखना न्यायिक प्रशासन के हित में नहीं होगा। जब जाँच शुरू की गई और अपराधी अधिकारी को दोषमुक्त कर दिया गया, यह सेवा में उनके बने रहने को सक्षम नहीं बनाएगा, अगर उनकी पृष्ठभूमि अन्यथा असंतोषजनक पाई जाती है। अधिकारी के खिलाफ कई शिकायतें की गईं और उनके खिलाफ चेतावनी भी जारी की गई। यह परिस्थितियों की समग्रता में है कि याचिकाकर्ता को न्यायिक अधिकारी के रूप में बने रहने का हकदार नहीं पाया गया है। विद्वान वकील ***उच्च न्यायालय, पटना बनाम पांडे मदन मोहन प्रसाद सिन्हा और अन्य (1997) 10 एससीसी 409*** पर भी भरोसा करेंगे। यह तर्क दिया गया था कि परिवीक्षाधीन की सेवाओं की समाप्ति पर केवल इस आधार पर सवाल उठाया जा सकता है कि यह मनमाना या दंडात्मक था और यदि न्यायिक सेवा

में बने रहने के लिए अनुपयुक्तता का पता चलता है, तो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को आकर्षित करने का कोई सवाल ही नहीं है। न्यायिक अधिकारी के खिलाफ बार-बार शिकायतें हमेशा न्यायिक अधिकारी की सेवाओं को समाप्त करने में एक विचार हो सकता है और यदि यह दंडात्मक या कलंकित नहीं पाया जाता है तो इसे दूषित नहीं किया जाएगा; यह सम्मोहक तर्क है।

9. मामले की प्रकृति और उच्च न्यायालय के इस दावे को ध्यान में रखते हुए कि समाप्ति सरलीकरण अधिकारी के साथ किसी भी कलंक के बिना जुड़ा हुआ है और अर्थ-दंड की प्रकृति में नहीं है, न्यायिक पदाधिकारी की सेवा पुस्तिका के आह्वाहन हेतु राजी किया जाए। हम स्वयं उच्च न्यायालय के जवाबी हलफनामे से भी ऐसा करने के लिए मजबूर थे, क्योंकि अनुलग्नक-ए के रूप में प्रस्तुत सेवा दस्तावेज से संकेत मिलता है कि अधिकारी को अपनी सेवा के पांच वर्षों की सभी तिमाहियों में लगातार उत्कृष्ट ग्रेड प्राप्त था; उनकी समाप्ति से पहले, ऐसी पांच साल की अवधि की पहली तिमाही की दूसरी तिमाही में एक 'खराब' टिप्पणी को छोड़कर।

10. याचिकाकर्ता को 26 वीं न्यायिक सेवा प्रतियोगी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद अस्थायी रूप से दीवानी न्यायाधीश (कनिष्ठ प्रभाग) के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्हें सासाराम (रोहतास) में दीवानी न्यायाधीश (कनिष्ठ प्रभाव) के रूप में 22.12.2007 को तैनात किया गया था और वे 04.01.2008 को परिवीक्षाधीन दीवानी न्यायाधीश (कनिष्ठ प्रभाग) के रूप में शामिल हुए। तब याचिकाकर्ता को वर्ष 2009 में बिक्रमगंज (रोहतास) में प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में तैनात किया गया था, जिस अवधि से उन्हें बकाया श्रेणी में रखा गया था। 27.06.2011 को, याचिकाकर्ता को छपरा में सारण में स्थानांतरित कर दिया गया और दो महीने के भीतर, समस्याएं शुरू हो गईं; क्योंकि उनके अनुसार जिला न्यायाधीश उनके प्रति शत्रुतापूर्ण थे।

11. जैसा कि अभिलेखों से उपलब्ध है, जबकि याचिकाकर्ता को बिक्रमगंज में प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में तैनात किया गया था, कुछ अधिवक्ताओं ने उनकी अदालत में मामलों पर विचार करने के संबंध में उनके खिलाफ शिकायतें कीं। यह शिकायत जिला न्यायाधीश द्वारा दिनांक 09.06.2011 को संसूचित किया गया कर अग्रसारित किया गया, जिसके आधार पर स्पष्टीकरण मांगा गया और स्थायी समिति ने 13.09.2011 को अपनी बैठक में अधिकारी को अपने व्यवहार में सावधान रहने और न्यायिक अलगाव बनाए रखने का निर्देश दिया। जबकि, एक और आरोप याचिका जिला न्यायाधीश द्वारा अपने दिनांक 19.08.2011 के संचार के माध्यम से अग्रेषित की गई थी। उठाए गए तीन आरोपों में से, एक शिकायत मामले से संबंधित पहला आरोप और दूसरे मामले को खारिज करने के संबंध में दूसरा आरोप, मामलों के रिकॉर्ड से टिकाऊ नहीं पाया गया। तीसरा आरोप अधिकारी द्वारा अदालत परिसर में एक मंदिर के निर्माण की अनुमति देने और वादियों से उसके लिए अभिदान लेने के संबंध में था। स्थायी समिति ने 17.01.2012 पर अपनी बैठक में तीसरे आरोप से संबंधित फाइलों को स्थायी समिति के समक्ष रखने का निर्देश दिया। दिनांक 1 की अपनी बैठक में, स्थायी समिति ने सिविल कोर्ट परिसर के भीतर मंदिर निर्माण की अनुमति देने और मंदिर निर्माण के लिए योगदान एकत्र करने के आरोप के संबंध में अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने का निर्देश दिया। जाँच रिपोर्ट अनुलग्नक-बी के रूप में प्रस्तुत की जाती है।

12. जाँच रिपोर्ट के अवलोकन से संकेत मिलता है कि बेंच क्लर्क अपराधी कर्मचारी ने अंशदान के संग्रह के संबंध में आरोप लगाया गया और अपदस्थ किया गया था कि रसीदें अपराधी अधिकारी द्वारा उन्हें दी गई थीं और उनके आदेश पर, रसीदें शुरू करने के बाद वादियों को रसीदें जारी की गईं और अधिकारी द्वारा पैसे रखे जाते थे। जिरह में उन्होंने कहा है कि आरोप अपराधी अधिकारी के स्थानांतरण के

बाद लगा है। ऑफिस क्लर्क, जिनसे गवाह नंबर 2 के रूप में पूछताछ की गई थी, ने भी सदस्यता के संग्रह के आरोप का समर्थन किया और गवाह नंबर 1 के समान ही गवाही दी। गवाह संख्या 3, एक अन्य अदालत कर्मचारी, ने हालांकि अपने स्पष्टीकरण की पहचान की, कहा कि उसने गवाह संख्या 1 और 2 के निर्देश पर वही लिखा था। जिरह में उन्होंने कहा कि जिला न्यायाधीश ने पीठासीन अधिकारी के अंगरक्षक को वापस ले लिया था और बिक्रमगंज एक संवेदनशील क्षेत्र था और अधिकारियों का आवास एक सुनसान जगह पर स्थित था। यह उनका बयान था कि मंदिर का निर्माण अपराधी अधिकारी के शामिल होने से पहले किया गया था।

13. दिलचस्प बात यह है कि शिकायतकर्ता, जितेंद्र कुमार सिंह, जिनसे गवाह संख्या 4 के रूप में पूछताछ की गई थी, ने शिकायत में स्वीकार किया, लेकिन जिरह में, उसने अंशदान के संग्रह के लिए अपराधी अधिकारी को कोई रसीद पुस्तिका देने से इनकार किया। शिकायत में उनके दावे के विपरीत। यह भी कहा गया कि उन्होंने जाँच अधिकारी कि अपराधी अधिकारी के खिलाफ कुछ भी स्थापित नहीं था, जो परिसर में निर्माण शुरु किया हो। उन्होंने यह भी कहा कि स्टेशन में अपराधी अधिकारी की तैनाती से पहले मंदिर का निर्माण किया जा रहा था और जिला न्यायाधीश स्वयं मंदिर निर्माण की निगरानी के लिए बिक्रमगंज में अदालत के परिसर का दौरा कर रहे थे। जब इलाके के लोगों ने निर्माण का विरोध किया और अन्य समुदायों ने भी परिसर के अंदर अपने धार्मिक मंदिरों के निर्माण की मांग की, तो जिला न्यायाधीश ने शिकायतकर्ता द्वारा दायर शिकायत प्राप्त की। जाँच अधिकारी ने पाया कि परिसर में निर्माण शुरू करने वाले अपराधी अधिकारी को खोजने के लिए कुछ भी स्थापित नहीं हुआ था। स्थायी समिति ने जांच रिपोर्ट को देखने के बाद अधिकारी को आरोपों से बरी कर दिया।

14. हम यह देखने के बिना नहीं रह सकते कि, दो गवाहों ने सदस्यता एकत्र किए जाने के बारे में बात की थी, लेकिन एक अन्य गवाह ने इसका खंडन किया; सभी अदालत के कर्मचारी। हम दोहराते हैं कि स्थायी समिति ने जांच रिपोर्ट को देखने के बाद अधिकारी को दोषमुक्त कर दिया। हम अभिलेखों से देखते हैं कि उच्च न्यायालय को अग्रेषित अन्य शिकायतें भी थीं, जिन्हें निरीक्षण न्यायाधीश द्वारा 'प्रेषित' किया गया था। जबकि मामले इस प्रकार बने रहे, रजिस्ट्री ने स्थायी समिति के समक्ष अधिकारी, एक मुन्सिफ (सिविल न्यायाधीश) (कनिष्ठ प्रभाग) को सुनिश्चित किया। याचिकाकर्ता, जो बिहार न्यायिक सेवा के 26 वें बैच के एक अधिकारी, न्यायिक मजिस्ट्रेट-सह-अतिरिक्त मुन्सिफ, छापरा के रूप में जारी था, ने विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के साथ-साथ दो साल से अधिक की सेवा पूरी की थी। याचिकाकर्ता को दिनांक 18.03.2014 के संचार के माध्यम से पहली वेतन वृद्धि भी दी गई थी। रोहतास से अलग संबंधित जिला और सत्र न्यायाधीश से उपरोक्त अधिकारी की एक फिटनेस रिपोर्ट भी स्थायी समिति के समक्ष रखी गई थी। सतर्कता प्रकोष्ठ, कानूनी प्रकोष्ठ, अभियोग सारणी और अवलोकन सारणी की रिपोर्ट भी स्थायी समिति के समक्ष रखी गई। अधिकारी के खिलाफ कोई विभागीय कार्यवाही लंबित नहीं थी और कोई आरोप या अवलोकन लंबित नहीं था। महानिबंधक ने भी कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की और जिला न्यायाधीश की रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया गया कि अधिकारी पुष्टि के योग्य है। हालांकि, स्थायी समिति ने 29.04.2014 को अपनी बैठक में सिफारिश की कि याचिकाकर्ता को बर्खास्त किया जाए और उसे सेवा से छुट्टी दे दी जाए। समिति की सिफारिश को पूर्ण न्यायालय द्वारा 14.05.2014 को अपनी बैठक में अनुमोदित किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप समाप्ति आदेश जारी किया गया था।

15. हम सबसे पहले *चुनाव के सिद्धांत* के आवेदन के प्रयोग को जहाँ तक देखते हैं कि किसी अधिकारी की परिवीक्षा की पुष्टि करने से इनकार करने के

पहलू के रूप में चुनाव का संबंध है; जिसकी सेवा असंतोषजनक पाई गई थी, दुराचार के आरोप के आधार पर जिसमें उसे अनुशासनात्मक कार्यवाही में दोषमुक्त कर दिया गया था, जिसमें निष्कर्ष अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा स्वीकार किए गए थे। यह सामान्य बात है कि समाप्ति सरलीकरणकर्ता को पारित करने में, भले ही कदाचार की शिकायत हो, नियुक्ति प्राधिकारी इस तरह के समाप्ति सरलीकरणकर्ता पर निर्णय ले सकता है, अधिकारी के खिलाफ जांच की कार्यवाही शुरू किए बिना, उठाई गई शिकायत के आधार पर, लेकिन समाप्ति आदेश के कलंकित या दंडात्मक होने के बिना। नियुक्ति प्राधिकारी की संतुष्टि जहां तक कि अधिकारी का रोजगार में बने रहने के लिए उपयुक्त नहीं होना या उसकी परिवीक्षा घोषित होने का हकदार नहीं होना, एक वस्तुनिष्ठ संतुष्टि है, जिसे अभिलेखों से उचित ठहराया जाना चाहिए। केवल यह तथ्य कि यह एक आरोप के आधार पर है कि परिवीक्षा घोषित नहीं की गई थी, परिणामी समाप्ति को दूषित नहीं करता है, यदि परिवीक्षा घोषित करने से इनकार करने वाला आदेश ऐसे आरोप का उल्लेख नहीं करता है। तब आदेश को एक समाप्ति सरलीकरणकर्ता के रूप में माना जाता है, जिसकी शिकायत नहीं की जा सकती है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 311 (2) के तहत शरण नहीं ली जा सकती है; विशेष रूप से एक परिवीक्षाधीन जिसे जारी रखने का कोई निहित अधिकार नहीं है, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकरण इस तरह के पद में योग्यता की पुष्टि की जानी चाहिए। ऐसा कोई कठोर और त्वरित नियम भी नहीं है कि एक बार कदाचार के आरोप के रूप में आरोप लगाए जाने और जांच पर विचार करने या शुरू करने के बाद, एक समाप्ति सरलीकरण नहीं किया जा सकता है; जांच को उसके तार्किक निष्कर्ष पर ले जाए बिना; यदि फिर से समाप्ति उपरोक्त के रूप में सरल है।

16. ***ट्रान्सकोर*** (उपरोक्त) में विद्वान न्यायाधीशों ने चुनाव के तीन तत्वों पर विशेष रूप से जोर दिया, अर्थात् (i) दो या दो से अधिक उपचारों का अस्तित्व, (ii)

ऐसे उपचारों के बीच विसंगतियां और (iii) उनमें से एक का विकल्प। अनुशासनात्मक जाँच के लिए कार्यवाही के उपचार को अपने आप में समाप्ति सरलीकरण के उपचार के साथ असंगत या प्रतिकूल नहीं कहा जा सकता है। लेकिन जब यह अपराधी के दोषमुक्त होने के साथ निष्कर्ष के बिंदु पर पहुंच जाता है, तो उसी आरोप के आधार पर एक और समाप्ति, जिसके आधार पर उसे दोषमुक्त किया गया था, असंगत हो जाती है और पहले किया गया विकल्प जिसका उसके तार्किक निष्कर्ष तक पालन किया गया था, नियोक्ता के खिलाफ खड़ा होगा और फिर उसी आरोप पर समाप्ति सरलीकरण का सहारा लेगा, जिस पर अपराधी को दोषमुक्त किया गया था। दुराचार के आरोप पर घरेलू जांच के साथ आगे बढ़ने और व्यक्ति को उक्त आरोप से दोषमुक्त किए जाने के बाद, योग्यता को ऐसे पद के वास्ते ठोस रुप से निश्चित किया गया।

17. हालाँकि, ऐसी अन्य शिकायतें भी हो सकती हैं जिन पर इस तरह की समाप्ति प्रभावित हो सकती है या लगातार खराब मूल्यांकन भी इसका कारण बन सकता है। वर्तमान मामले में, हम पाते हैं कि ऐसी कोई शिकायत मौजूद नहीं थी या स्थायी समिति के समक्ष रखी गई थी, जो स्थायी समिति को इस तरह के निष्कर्ष पर आने में सक्षम बनाती। हमने उच्च न्यायालय के जवाबी हलफनामे में अनुलग्नक-ए के रूप में पेश किए गए अधिकारी के सेवा संचिका पर भी ध्यान दिया है, जिसमें उनकी सेवा समाप्ति से ठीक पहले, उन्हें लगातार साढ़े चार साल, सभी अठारह तिमाहियों के लिए बकाया घोषित किया गया है।

18. ***पांडे मदन मोहन प्रसाद सिन्हा*** (ऊपर) एक ऐसा मामला था जिसमें 1976-77 से 1981-82 तक लगातार वर्षों में प्रतिकूल टिप्पणियों के साथ अधिकारी का मूल्यांकन किया गया था। निरीक्षण करने वाले न्यायाधीश ने अधिकारी के आचरण और पूर्ववृत्त के बारे में भी टिप्पणी की थी, जो एक न्यायिक अधिकारी के लिए बहुत अवांछनीय और अशोभनीय बताया गया था। उनके न्यायिक कार्य में उनकी ईमानदारी

को छूते हुए शिकायतें, उनके चरित्र और नैतिकता के बारे में गंभीर शिकायतें, नशे में धुत होने के आरोप और उनके साथ ताश खेलकर इलाके के विभिन्न व्यक्तियों के साथ बातचीत जारी रखने की शिकायतें भी थीं। अन्य वर्षों की प्रतिकूल टिप्पणियों को बाद में समाप्ति के लिए सूचित किया गया था, जो आवश्यक नहीं पाया गया था और यह माना गया था कि इससे सेवाओं की समाप्ति की कार्रवाई इस आधार पर दूषित नहीं होनी चाहिए कि अधिकारी मुन्सिफ के पद पर पुष्टि के लिए उपयुक्त नहीं था। विद्वान न्यायाधीशों ने अच्छी तरह से स्थापित कानून को स्पष्ट किया कि एक परिवीक्षाधीन को किसी पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है और उसे किसी ऐसे कर्मचारी के बराबर नहीं माना जा सकता है जिसे मूल रूप से किसी पद पर नियुक्त किया गया हो, जिसकी सेवाओं से समाप्ति के लिए संविधान के अनुच्छेद 311 (2) के तहत प्रावधानों का पालन करना आवश्यक होगा। 1976-77 एवं 1979-80 की टिप्पणियों से अधिकारी को संसूचित किया गया एवं यह उसे बर्खास्त करने के उच्च न्यायालय के निर्णय से पूर्व था। सेवाओं को समाप्त करने का आदेश पारित होने से पहले सुनवाई का भी कोई अधिकार नहीं है, यह स्पष्ट निष्कर्ष था।

19. हालांकि, हम वर्तमान मामले में समानांतर नहीं है, जहां तक याचिका को विशिष्ट ग्रेड, सभी चार सालों में उसके सेवा के समाप्ति के ठीक पहले दिया गया था एवं यह साढ़े चार साल के तीमाही में ग्रेडिंग के पूर्व सुसंगत पाया गया। उनके खिलाफ कोई शिकायत या अनुकूल टिप्पणी असतित्व में नहीं था। जैसा कि हमने पूर्व में ध्यान दिया है, केवल एक चेतावनी जो अनुलग्नक-12 द्वारा सुस्पष्ट किया गया था, जिसके बाद बहुत समय निकल गया था। जिला न्यायाधीश जिसके तहत याचिकाकर्ता काम कर रहा था, ने भी उन्हें फिर करने के लिए अनुशंसा की थी। अभिलेख पर कुछ भी उपलब्ध नहीं था, जिसके स्थायी समिति के आदेश ठोस रखा जा सके। उनके खिलाफ शुरु किए गए एक अनुशासनात्मक कार्रवाई को समाप्त किया गया

था। स्थायी समिति के आदेश को स्थिर रखने हेतु कुछ भी उपलब्ध नहीं था।

20. **एम.एस. बिंद्रा** (ऊपर दिया गया) एक ऐसा मामला था जिसमें कर्तव्य में अपने समर्पण और दृढ़ता के लिए सम्मानित एक अधिकारी को अचानक अविश्वसनीय सत्यनिष्ठा और सरकारी सेवा में जिम्मेदारी के किसी भी पद के लिए अयोग्य करार दिया गया था; जिसके निष्कर्ष पर, उसे अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर दिया गया था। राजस्व विभाग में अधिकारी के बने रहने पर विचार करते हुए जांच समिति द्वारा उनके खिलाफ तीन विशिष्ट मामले दर्ज किए गए थे। यह पाया गया कि जांच समिति द्वारा जिन उदाहरणों पर भरोसा किया गया है, उनमें से कोई भी अधिकारी की ओर से किसी भी आपत्तिजनक आचरण को प्रकट नहीं करता है और इसके विपरीत, यह केवल संगठन में उनकी प्रतिष्ठा को बढ़ाता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ***भारतीय संघ बनाम कर्नल जे.एन. सिन्हा, (1970) 2 एस सी सी 458*** मामले में जहाँ यह घोषणा की कि यदि उपयुक्त प्राधिकारी प्रामाणिक रूप से अपेक्षित राय बनाता है, तो उसकी राय को अदालतों के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती है, हालांकि यह तर्क देने के लिए खुला है कि अपेक्षित राय नहीं बनाई गई है या संपार्श्विक आधारों पर आधारित है और यह एक मनमाना निर्णय है। ***बैकुंठा नाथ दास बनाम मुख्य जिला चिकित्सा पदाधिकारी,(1992)2 एस सी सी 299,*** एक तो न न्यायाधीशों की पीठ तो उपरोक्त उक्ति का पालन करते हुए, अनिवार्य सेवानिवृत्ति के मामले पर विचार करते हुए, पाँच सिद्धांत निर्धारित किए गए, जिनमें से सं. (iii) नीचे निकाला गया हैः

> "(iii) अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश के संदर्भ में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का कोई स्थान नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि न्यायिक जांच को पूरी तरह से बाहर रखा गया है। यद्यपि उच्च न्यायालय या यह न्यायालय एक अपीलीय न्यायालय के रूप में मामले की जांच नहीं करेगा, वे हस्तक्षेप कर सकते हैं यदि वे संतुष्ट हैं कि आदेश पारित किया गया है (ए) दुर्भावनापूर्ण या (बी) यह किसी

> साक्ष्य पर आधारित नहीं है या (सी) यह मनमाना है-इस अर्थ में कि कोई भी उचित व्यक्ति द्वारा दी गई सामग्री पर अपेक्षित राय नहीं बनाएगा; संक्षेप में, यदि यह एक विकृत आदेश पाया जाता है। "

21. ***एम.एस. बिंद्रा*** (ऊपर) में, इसे पैरा-11 में आयोजित किया गया था, जिसे नीचे निकाला गया हैः

> **"11.** इसलिए, समय से पहले अनिवार्य सेवानिवृत्ति को लागू करने वाले किसी भी आदेश की न्यायिक जांच की अनुमति है यदि आदेश या तो मनमाना या दुर्भावनापूर्ण है या यदि यह किसी भी सबूत पर आधारित नहीं है। यह अवलोकन कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति के संदर्भ में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का कोई स्थान नहीं है, इसका मतलब यह नहीं है कि यदि सही निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए अपराधी अधिकारी का संस्करण आवश्यक है, तो इसे इस धारणा पर खारिज किया जा सकता है कि केवल अन्य सामग्रियों पर विचार करने की आवश्यकता है। "

उस मामले में हालाँकि अपीलार्थी ने यह दिखाने का प्रयास किया था कि जाँच समिति के सदस्यों में से एक पर दुर्भावना थी, लेकिन इस तरह के विवाद को खारिज कर दिया गया था।

22. वर्तमान मामले में भी, अभिलेख जिला न्यायाधीश के खिलाफ एक आरोप का खुलासा करते हैं, जिन्होंने शिकायत को उच्च न्यायालय को भेज दिया था। हम यह देखने के बिना नहीं रह सकते कि जाँच में, शिकायतकर्ता ने स्वयं जिला न्यायाधीश के खिलाफ और शिकायत को जिला न्यायाधीश द्वारा उकसाया जाना स्वीकार किया। हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि दोनों गवाह संख्या 1 और 2, जिन्होंने अपराधी अधिकारी द्वारा ली जा रही सदस्यता पर गवाही दी थी, वे जांच के समय भी खास जिला न्यायाधीश के अधीन सेवारत थे। हम यह कहते हैं, इसके बावजूद, जैसा कि हमने देखा, स्थायी समिति ने भी जांच रिपोर्ट के अवलोकन के बाद पाया कि अधिकारी लगाए गए आरोपों से दोषमुक्त होने का हकदार है और जिला

न्यायाधीश के खिलाफ लगाए गए शत्रुता और द्वेष के आरोप में जाने की आवश्यकता नहीं है। यह मामूली बात है कि अनुशासनात्मक प्राधिकारी के पास जांच में दिए गए साक्ष्य में जाने और कथित कदाचार के लिए एक अपराधी अधिकारी को दोषी ठहराने की क्षमता होगी; भले ही जांच अधिकारी अपराधी को दोषमुक्त कर दे। एकमात्र आवश्यकता यह होगी कि जांच रिपोर्ट में निष्कर्षों से विचलन के कारणों को बताना होगा और अपराधी अधिकारी को इस तरह बताए गए कारणों के खिलाफ स्पष्टीकरण और प्रतिनिधित्व करने का अवसर दिया जाएगा। वर्तमान मामले में स्थायी समिति द्वारा ऐसा कोई प्रयास नहीं किया गया था।

23. अभिलेखों को देखने के बाद, हमें ऐसी कोई सामग्री नहीं मिलती है जिस पर स्थायी समिति याचिकाकर्ता की परिवीक्षा की पुष्टि से इनकार कर सकती थी, जिसके परिणामस्वरूप उनकी सेवाएँ समाप्त की जा सकती है। एक समाप्ति सरलीकरणकर्ता, यदि वह दंडात्मक नहीं है या कोई कलंक नहीं डालता है, तो उसे परिवीक्षाधीन द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती है, विशेष रूप से क्योंकि उसे पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों के बारे में उसने खुद कहा कि अनुशासनात्मक जांच भी आवश्यक नहीं होगी, लेकिन सवाल यह है कि क्या नियुक्ति/अनुशासनात्मक प्राधिकारी के अप्रत्यक्ष आदेश पर ऐसी समाप्ति की जा सकती है। यह सामान्य बात है कि जब किसी परिवीक्षाधीन के खिलाफ आरोप लगाए जाते हैं, तो नियुक्ति प्राधिकरण या तो अनुशासनात्मक जांच कर सकता है या आरोपों के आधार पर, बिना किसी स्पष्टीकरण के भी, किसी कर्मचारी की सेवाओं को उसकी परिवीक्षा की पुष्टि किए बिना समाप्त कर सकता है। लेकिन अभिलेखों में कुछ सामग्री उपलब्ध होनी चाहिए ताकि नियुक्ति प्राधिकारी को वस्तुनिष्ठ संतुष्टि मिल सके कि कर्मचारी को सेवा में जारी रखना प्रशासन के हित में नहीं होगा; यहाँ, न्यायिक सेवा में। यह कहना कि समाप्ति को ही सरलीकरण कहा जाता है, न तो दंडात्मक और न

ही कलंकित करने वाला, इसका मतलब यह नहीं है कि निर्णय किसी प्रासंगिक सामग्री पर आधारित नहीं होना चाहिए, न तो किसी आरोप या खराब प्रदर्शन पर। जब इस तरह से समाप्त करने के निर्णय को चुनौती दी जाती है, तो नियुक्ति प्राधिकरण को न्यायालय को संतुष्ट करने में सक्षम होना चाहिए कि यह उचित आधारों पर समाप्ति का आदेश दिया गया था और यदि उच्च न्यायालय सी. डब्ल्यू. जे. सी. में पर्याप्त समकालीन सामग्री मौजूद है। अभिलेखों में, तब न्यायालय इस तरह से समाप्ति की सलाह पर विचार नहीं करेंगे; तब से न्यायालय नियोक्ता की राय के लिए अपनी राय को प्रतिस्थापित करेगा, जो अनुज्ञेय नहीं है। वर्तमान मामले में ऐसी सामग्री का पूर्ण अभाव है।

24. हमें **अभय जैन** (ऊपर) को भी देखना होगा, जिस पर याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा बहुत अधिक भरोसा किया गया था। इसमें, बर्खास्त कर्मचारी एक न्यायिक अधिकारी था, जिसने वर्ष 2013 में सेवा में प्रवेश किया और 2016 में उसे छुट्टी दे दी गई। आरोपमुक्त करने का आधार भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत एक मामले में अपीलार्थी द्वारा दी गई जमानत भी थी। आरोप यह था कि अधिकारी ने अभियोजन की मंजूरी का इंतजार नहीं किया और उसी आरोपी को जमानत देने से इनकार करने वाले उच्च न्यायालय के आदेश की अनदेखी की गई। अधिकारी ने मंजूरी प्रस्तुत करने के लिए मामले को स्थगित कर दिया, अंततः एक अपीलार्थी को जमानत दे दी, विशेष रूप से यह देखते हुए कि एक सह-अभियुक्त को उच्च न्यायालय द्वारा जमानत दी गई थी। यह आरोप लगाया गया था कि जिला न्यायाधीश द्वारा जमानत की मंजूरी उच्च न्यायालय द्वारा जमानत याचिका को खारिज करने के बाद दी गई थी; जिसे बचाव में, जिला न्यायाधीश के समक्ष पेश नहीं किया गया था। हालांकि एक जांच शुरू की गई थी, जबकि वह लंबित थी, अधिकारी को पूर्ण न्यायालय के इस निष्कर्ष पर आरोपमुक्त कर दिया गया था कि

अपीलार्थी की सेवाएं परिवीक्षा के दौरान,हालाँकि, जाँच को फिर से खोलने के अधिकार के अधीन बंद कर दिया गया था।

25. **अभय जैन** (उपरोक्त) मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के इस तर्क को स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि अपीलार्थी का आरोपमुक्त होना एक निर्वहन सरलीकरण था और अनुच्छेद 311 (2) का उल्लंघन नहीं था। यह पाया गया कि उच्च न्यायालय यह तर्क देने में विफल रहा कि कैसे जमानत आदेश से संबंधित कदाचार का आरोप आरोपमुक्त करने के आदेश का आधार नहीं था; विशेष रूप से जब एक जांच शुरू की गई थी और यह आरोपमुक्त होने के समय लंबित थी। माननीय उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायिक समिति के समक्ष रखी गई सामग्री का भी उल्लेख किया, जिसने अपीलार्थी को आरोपमुक्त करने की सिफारिश की थी, जिसमें जमानत देने के संबंध को छोड़कर अपीलार्थी के खिलाफ प्रतिकूल टिप्पणियों का पूर्ण अभाव था। अपीलार्थी के कार्य और आचरण का लगातार अच्छा मूल्यांकन किया गया और उसकी सत्यनिष्ठा पर कभी संदेह नहीं किया गया। वर्ष 2013 के लिए अधिकारी के ए. सी. आर. ने उनका मूल्यांकन बहुत अच्छा किया और विशेष रूप से उल्लेख किया कि उनकी ईमानदारी पर कभी संदेह नहीं किया गया था, जिसका पालन वर्ष 2014 (भाग-1) में भी किया गया था। 2014 के दूसरे भाग में हालांकि उनका मूल्यांकन अच्छा किया गया था, लेकिन न्यायिक कार्य में सुधार के लिए एक टिप्पणी की गई थी, जो जारी जमानत आदेश पर भी आधारित पाई गई थी। उच्च न्यायालय ने वर्ष 2015 की एसीआर पर भरोसा किया था जिसमें प्रशासनिक न्यायाधीश ने दर्ज किया था कि *"अधिकारी की ईमानदारी संदिग्ध है। मेरे समग्र मूल्यांकन में, मैं अधिकारी का औसत मूल्यांकन करता हूँ "* ; जो प्रविष्टि अधिकारी के निर्वहन के बाद था।

26. माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह स्वीकार करने से इनकार कर

दिया कि यह बाद की इन टिप्पणियों पर आधारित था कि आरोपमुक्त किया गया था; क्योंकि वे अपीलार्थी को सेवा से मुक्त किए जाने के बाद किए गए थे। यह स्पष्ट रूप से पाया गया कि अधिकारी के रिकॉर्ड में कुछ भी प्रतिकूल नहीं था और उच्च न्यायिक समिति द्वारा आरोपमुक्त करने की पूरी सिफारिश जमानत आदेश के पारित होने पर आधारित थी, जिसके लिए एक जांच शुरू की गई थी, लेकिन जारी नहीं रखी गई थी। जमानत देने पर, अभिलेखों से पता चला कि अभियोजन पक्ष को मंजूरी को अभिलेख पर लाने के लिए पर्याप्त समय दिया गया था, जो नहीं किया गया था। जाँच अधिकारी ने केवल संकेत दिया कि फाइल को मंजूरी के लिए राज्य सरकार को प्रस्तुत किया गया है। उच्च न्यायालय द्वारा उक्त अभियुक्त को जमानत देने से इनकार करने को भी न्यायालय के समक्ष रिकॉर्ड में नहीं रखा गया था। इन सबसे ऊपर, सह-अभियुक्त को उच्च न्यायालय द्वारा जमानत दी गई थी, जो अधिकारी द्वारा दिए गए अनुदान में भी एक प्रासंगिक विचार था। जिस जमानत पर आरोप लगाए गए थे, वह दोषपूर्ण नहीं पाया गया क्योंकि यह आपराधिक प्रक्रिया, भले ही उच्च न्यायालय द्वारा जमानत के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया हो। अधिकारी को सेवा की निरंतरता और वरिष्ठता सहित सभी परिणामी लाभों के साथ बहाल किया गया था, लेकिन केवल 50 प्रतिशत वेतन का हकदार पाया गया।

27. हम ध्यान दे सकते हैं कि **अभय जैन** (उपरोक्त) में कम से कम, अधिकारी के खिलाफ जमानत देने का आरोप लंबित था, जिसके आधार पर आरोपमुक्त किया गया था। वर्तमान मामले में, उनके खिलाफ कोई आरोप या शिकायत लंबित नहीं थी और कोई अनुशासनात्मक जांच भी लंबित नहीं थी। उनके खिलाफ एकमात्र प्रतिकूल टिप्पणी वर्ष 2011 की थी और दुर्व्यवहार के आरोपों पर शुरू की गई जांच याचिकाकर्ता के दोषमुक्त होने के साथ समाप्त हो गई। अधिकारी के खिलाफ सात अन्य शिकायतें

थीं, जिनमें से किसी पर भी कार्रवाई नहीं की गई। अधिकारी को उनकी समाप्ति से ठीक पहले 18 तिमाहियों में उनके एसीआर में लगातार 'उत्कृष्ट' श्रेणी दी गई थी।

28. मामले के अभिलेखों और उच्च न्यायालय द्वारा हमारे समक्ष रखे गए अभिलेखों को देखने के बाद, हमारी राय है कि स्थायी समिति के पास अधिकारी की सेवाओं को समाप्त करने के लिए कोई सामग्री उपलब्ध नहीं थी, जिसमें परिवीक्षा घोषित करने से इनकार किया गया था ताकि याचिकाकर्ता को उस पद पर पुष्टि की जा सके जिसमें उसे नियुक्त किया गया था।

29. हम पारित आदेश को दरकिनार करते हैं और याचिकाकर्ता को सभी परिणामी लाभों, वरिष्ठता और सेवा में निरंतरता के साथ बहाल करने का निर्देश देते हैं, हालांकि, पिछला वेतन 50 प्रतिशत तक सीमित रखते हैं ।

30. रिट याचिका की अनुमति दी जाती है और पक्षों को अपनी-अपनी लागत वहन करने के लिए छोड़ दिया जाता है।

(के. विनोद चंद्रन, मुख्य न्यायमूर्ति)

न्यायमूर्ति पार्थ सारथी : मैं सहमत हूँ

(पार्थ सारथी, न्यायमूर्ति)

सुजीत/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।